प्रधानमंत्री से भजनलाल व मदन राठौड़ की मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल की चर्चा तेज हुई

कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रस्तावित फेरबदल की विस्तृत जानकारी दी

जयपुर, 2 दिसम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने मंगलवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात को राजस्थान के राजनीतिक हलकों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चर्चा है कि मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल में प्रस्तावित फेरबदल के बारे में प्रधानमंत्री को विस्तृत जानकारी दी है और हरी झंडी मिलने के बाद राज्य में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार या बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की, जिससे राजनीतिक अटकलें और तेज हुई हैं।

मुख्यमंत्री शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी को 10 दिसंबर को जयपुर में होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह में आमंत्रित किया है। पिछले साल राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान, हर साल प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इस बार इसका पहला आयोजन जेईसीसी, जयपुर में होगा, जिसका उद्देश्य दुनियाभर में बसे प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ना और उनके योगदान का सम्मान करना है। राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन भी पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व विभिन्न केन्द्रीय मंत्रियों से मुलाकात की।

राज्य में भजनलाल सरकार के दो वर्ष पूरे होने को हैं, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां लंबित हैं। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार पहले ही पूरा हो चुका है, जबकि राजस्थान और मध्यप्रदेश में चर्चा जारी है। गुजरात में हाल ही में पूरे मंत्रिमंडल में हुए बड़े बदलाव के बाद राजस्थान में भी इसी तरह के राजनीतिक बदलाव की संभावना पर सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की नई टीम घोषित होने के बाद राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए बाकी नेताओं व पदाधिकारियों को समायोजित किए जाने की तैयारी भी चल रही है।

- **प्रधानमंत्री के बाद, मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष की केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह व भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा से मुलाकात के कारण राजनीतिक अटकलें और तेज हो गईं।**
- **इसी क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा बुधवार को 3 बजे मंत्रिमंडल व 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाने को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।**

मुख्यमंत्री ने बुधवार को महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक बुलाई है। सचिवालय में दोपहर 3 बजे मंत्रिमंडल और 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। माना जा रहा है कि इन बैठकों में कई अहम फैसले किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री का पांच दिनों में दिल्ली का यह दूसरा दौरा था।

'संचार साथी ऐप अनिवार्य नहीं है, आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं'

संचार मंत्री ज्योतिरादित्य ने इस एप को लेकर चल रही आशंकाएं दूर करने की कोशिश की

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 दिसंबर। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को संचार साथी ऐप से जुड़ी चिंता को दूर करने का प्रयास किया और कहा कि "संचार साथी" ऐप अनिवार्य नहीं है और उपयोगकर्ता इस पर रजिस्टर न करने या, यहाँ तक कि, इसे डिलीट करने का विकल्प भी चुन सकते हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं की गोपनीयता उल्लंघन की आशंकाएं बनी हुई हैं।

28 नवंबर को, दूरसंचार विभाग ने मोबाइल हैंडसेट के निर्माताओं और आयातकों को निर्देश जारी किए थे कि वे भारत में उपयोग के लिए निर्धारित मोबाइल फोन पर इस ऐप को प्री इंस्टॉल करें, और पहले से निर्मित और बेचे गए उपकरणों पर सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से 90 दिनों के भीतर "संचार साथी" ऐप को पुश करें। सिंधिया ने कहा कि इस ऐप का विकास धोखाधड़ी कनेक्शनों की पहचान, चोरी हुए फोन का पता लगाने और सुरक्षा लागू के लिए बनाया गया है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यह ऐप जासूसी या कॉल की निगरानी करने में सक्षम नहीं है।

- **जब से सरकार ने "संचार साथी ऐप" प्री इंस्टाल करने और सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इसे पुश करने के लिए मोबाइल कंपनियों को अल्टीमेटम दिया है, तब से आशंकाओं का बाज़ार गर्म है और विपक्ष सरकार पर लोगों के मोबाइल फोन में "स्नूपिंग" का आरोप लगा रहा है।**
- **कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई पुराने मामले उठाकर संचार साथी ऐप के स्नूपिंग ऐप होने की आशंका जताई। प्रियंका गांधी ने भी इसे जासूसी की कोशिश करार दिया।**
- **हालांकि, सरकार का कहना है कि यह ऐप धोखाधड़ी वाले फोन कॉल्स, खोए फोन का पता लगाने व फोन की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पर, फिलहाल सरकार की दलील पर भारी संदेह है।**

विपक्षी नेता इससे सहमत नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "सरकार का यह एकतरफा कदम, बिना किसी को विश्वास में लिए ऐप को प्रीलोड करना, तानाशाही जैसा है। उनके तर्क सरकार के निजी स्वतंत्रता को कुचलने के पूर्व प्रयासों से संबंधित धारणाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा, "सरकार ने डिजिटल गोपनीयता को कुचलने के लिए कदम उठाए, जिससे रोज़ाना की ऑनलाइन गतिविधियाँ 24X7 निगरानी क्षेत्र में बदल गईं। सरकार ने डीपीडीपी एक्ट में संशोधन के माध्यम से आरटीआई ढाँचे का गला घोंटा और पैगसस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों और दूसरों पर जासूसी करने के लिए किया।"

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने संचार साथी को एक "स्नूपिंग ऐप" कहा, और कहा कि वर्तमान शासन देश को हर रूप में तानाशाही में बदलने की कोशिश कर रहा है। शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस घटनाक्रम को एक और "बिग बॉस निगरानी क्षण" करार दिया।

यह आशंकाएं पूरी तरह से निराधार नहीं हैं। "संचार साथी" की आधिकारिक नीति के अनुसार, कोई भी व्यक्तिगत डेटा उपयोगकर्ताओं को सूचित किए बिना एकत्र नहीं किया जाएगा, और यदि जानकारी एकत्र की जाती है, तो इसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अलावा किसी अन्य एजेंसी या व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया जाएगा। इसी समय, पॉलिसी पेज यह भी स्पष्ट करता है कि इस ऐप को कार्य करने के लिए भारी ड्यूटी एक्सेस की आवश्यकता होती है। इसमें कॉल करने और प्रबंधित करने, एसएमएस भेजने, कॉल और एसएमएस लॉग, कैमरा, फ़ंक्शन और फोटो और फाइलों तक पहुँच जैसी अनुमतियाँ शामिल हैं।

एक अन्य कांग्रेस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कर रहे हैं, जो यह दावा करते हैं कि मेवाड़ क्षेत्र पर उनका प्रभाव है।

मेवाड़ में 7 ज़िले हैं- उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, सलूंबर और प्रतापगढ़।

इन 7 ज़िलों में स्थिति इस प्रकार है:

तीन ज़िला अध्यक्ष आदिवासी समुदाय से हैं (उदयपुर ग्रामीण, डूंगरपुर और बांसवाड़ा)।

दो ज़िला अध्यक्ष राजपूत समुदाय से हैं (उदयपुर शहर और चित्तौड़गढ़)।

एक ज़िला अध्यक्ष ब्राह्मण समुदाय से है (सलूंबर- परमानंद मेहता)।

प्रतापगढ़ ज़िले में अध्यक्ष की नियुक्ति लंबित है, क्योंकि दो राजपूत उम्मीदवार- दिग्विजय सिंह और भानु प्रताप सिंह दावेदार हैं।

- **मेवाड़ में नियुक्तियों पर प्रभारी रंधावा वो ही कर रहे हैं, जो डॉ. सी.पी. जोशी व अन्य एक दो वरिष्ठ नेता चाहते हैं।**
- **अब झारखंड राज्य भी कांग्रेस के हाथ से निकल गया और राजस्थान में भी ट्राइबल्स व ओबीसी कांग्रेस के खिलाफ रहे थे, यह स्थिति ढाई साल बाद राजस्थान में होने वाले चुनाव में कांग्रेस को झटका दे सकती है।**

सात में से तीन-चार डीसीसी अध्यक्षों का राजपूत समुदाय से होना, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अच्छा संदेश नहीं देता। वैसे भी, अधिकांश राजपूत वोटर भाजपा के समर्थक माने जाते हैं।

उदयपुर संभाग में अधिकांश वोटर अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय से हैं, और दूसरी सबसे बड़ी संख्या ओबीसी मतदाताओं की है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरे मेवाड़ में एक भी ओबीसी ज़िला अध्यक्ष नहीं है। यहाँ तक कि राजसमंद ज़िला, जहाँ अभी नियुक्तियाँ लंबित हैं, वहाँ भी जो नाम सूचीबद्ध किया गया है, वह राजपूत समुदाय से है और सीपी जोशी का करीबी है।

रंधावा लंबे समय से राजस्थान के प्रभारी हैं। लेकिन चूंकि वह डोटासरा, जोशी और गहलोत के गुट का हिस्सा हैं, इसलिए वे उन्हीं की लाइन पर काम कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में, वह न केवल कांग्रेस को नुकसान पहुँचा रहे हैं बल्कि राहुल गांधी के एजेंडा को भी कमज़ोर कर रहे हैं।

राजसमंद ज़िले में ओबीसी समुदाय को अध्यक्ष पद देना ज़्यादा उचित होगा।

लोकसभा में 9 और 10 दिसम्बर को एसआईआर पर चर्चा होगी

लोकसभा अध्यक्ष के साथ बैठक में विपक्ष और सरकार में सदन चलाने की सहमति बनी

नयी दिल्ली, 02 दिसंबर। विपक्ष और सरकार के बीच संसद में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा को लेकर बना गतिरोध आज समाप्त हो गया। दोनों पक्षों में लोकसभा में आगामी मंगलवार और बुधवार को चुनाव सुधारों पर चर्चा कराने को लेकर सहमति बन गयी है।

इस सहमति के बाद उम्मीद है कि बुधवार को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी। सोमवार से शुरु हुए शीतकालीन सत्र के पहले दो दिन विपक्षी सदस्यों ने एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग को लेकर दोनों सदनों में भारी हंगामा किया, जिसके कारण कामकाज बाधित हुआ।

गतिरोध को देखते हुए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज दिन में विपक्षी दलों के सदन के नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिसमें यह सहमति बनी। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सोमवार को दोपहर 12 बजे से लोकसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ तथा मंगलवार को दोपहर 12 बजे से चुनाव सुधारों पर चर्चा की जाएगी।

- **इस सहमति के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि बुधवार से लोकसभा सुचारु रुप से चलेगी।**

इससे पूर्व, आज दूसरे दिन दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच भी रिजिजू ने कहा था कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को, चर्चा कब कराई जाएगी इसको लेकर कड़ा रुख नहीं अपनाना चाहिए। सभी मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और सरकार किसी भी मुद्दे पर नियमों के अनुरूप चर्चा कराने को तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा तुरंत कराने की अपनी बात अड़ा हुआ था।

पायलट को बचाने के स्वदेशी एस्केप सिस्टम का ट्रायल सफल

नई दिल्ली, 2 दिसंबर। सैन्य क्षेत्र में भारत ने आत्मनिर्भरता का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने लड़ाकू विमान की एस्केप प्रणाली का एक सफल उच्च-गति रॉकेट-स्लेड परीक्षण किया है, जिसकी जानकारी रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को दी। स्वदेशी लड़ाकू विमान की सुरक्षा तकनीक के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। रक्षा मंत्रालय की ओर से एक्स पर इस परीक्षण का एक वीडियो साझा किया गया है, जिसमें बताया गया है कि यह टेस्ट चंडीगढ़ में टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज सुविधा में 800 किमी/घंटे कंट्रोल्ड स्पीड पर किया गया था। इस सफल परीक्षण के बाद भारत दुनिया के उन चंद देशों में शामिल हो गया है, जिनके पास पायलट इजेक्ट सिस्टम की यह जटिल प्राणाली है।

जासूसी के केस में ब्रह्मोस के वैज्ञानिक निशांत प्रदीप अग्रवाल को बड़ी राहत

मुंबई, 2 दिसंबर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने मंगलवार को जासूसी मामले में ब्रह्मोस एयरोस्पेस के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक निशांत प्रदीप कुमार अग्रवाल को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा रद्द कर दी। हालांकि, अदालत ने लापरवाही के लिए उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा। निशांत पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ गोपनीय मिसाइल संबंधी जानकारी साझा करने का आरोप था।

- **बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी आजीवन कारावास की सजा रद्द कर दी पर लापरवाही मामले में उन्हें दोषी माना है।**

पिछले वर्ष जून में यहां की एक सत्र अदालत ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व इंजीनियर निशांत प्रदीपकुमार अग्रवाल को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अग्रवाल को 2018 में गिरफ्तार किया गया था।

उनकी दोषसिद्धि को आंशिक रूप से पलटते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह दिखाने में विफल रहा कि उन्होंने (निशांत) भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संरक्षा को खतरे में डालने या समाज में आतंक फैलाने जैसा कोई कार्य किया हो। न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति प्रवीण पाटिल की खंडपीठ ने सोमवार को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (ओएसए) के प्रमुख आरोपों से निशांत अग्रवाल को बरी कर दिया और उनकी उम्रकैद की सजा भी रद्द कर दी।

एसआईआर के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दिया गया। सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि सोरेन ने चुपचाप दिल्ली में वरिष्ठ भाजपा नेताओं से मुलाकातें की हैं, जिससे उनकी संभावित राजनीतिक नज़दीकियों की अटकलें तेज़ हो गई हैं। भले ही कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है, लेकिन इन मुलाकातों से विपक्षी एकता की कमजोर स्थिति साफ़ दिखाई देती है।

ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पहले ही कांग्रेस-नेतृत्व वाली सामूहिक रणनीति से दूरी बना चुकी है और कई राष्ट्रीय मुद्दों पर समानान्तर रुख रखती है। उधर अरविंद केजरीवाल की आप खुलकर कह चुकी है कि वह अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, जिससे कभी महत्वाकांक्षी रहा यह गठबंधन और कमज़ोर हो गया है।

यह बिखराव ऐसे समय हो रहा है जब भाजपा, कांग्रेस को अपने मुख्य राष्ट्रीय प्रतिद्वंदी के रूप में देखती है। भाजपा की रणनीति के अनुसार, क्षेत्रीय दल उनकी बढ़ती ताकत के लिए बड़ा खतरा नहीं हैं; असली चुनौती कांग्रेस ही है, जो कई राज्यों में भाजपा की राजनीतिक तौर-तरीकों और वोट बैंक को टक्कर दे सकती है। आंतरिक अविश्वास बढ़ने और छोटे सहयोगियों के दूर होने के साथ, इंडिय गठबंधन अब एक निर्णायक एवं महत्वपूर्ण परीक्षा से गुजर रहा है।

यह गठबंधन फिर से एकजुट हो पाएगा या शुरुआती दरारें बड़े टूटन का रूप लेंगी, यही सवाल शीतकालीन सत्र की राजनीतिक हलचल पर छाया हुआ है।

एयरपोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जिससे चेक-इन प्रक्रिया धीमी हो गई। हालांकि अब सिस्टम धीरे-धीरे ठीक हो रहा है, लेकिन स्थिति पूरी तरह सामान्य होने में अभी थोड़ा समय लग सकता है।

इसके साथ, एअर इंडिया ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी उड़ान की स्थिति (फ्लाइट स्टेटस) जरूर जांच लें।

नाबालिग ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि घटना के दिन अभियुक्त ने उससे वेलेन्टाइन डे सेलिब्रेट करने का कहकर घर आने को कहा था, किसी को बिना बताए वो चली गई थी। इसके बाद अभियुक्त ने उसे नशीली मिठाई खिलाई। जब उसे होश आया तो वह दिल्ली में थी। यहां अभियुक्त ने उसके साथ कई बार संबंध बनाए। बाद में पुलिस के कहने पर अभियुक्त उसे वापस ले आया था।

अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि उसे इस मामले में रंजिशवश फंसाया जा रहा है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

इंडिया गठबंधन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर विचार विमर्श करेंगे।

गौरतलब है कि मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में संसद भवन में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें विपक्ष की मांग को मानते हुए, लोकसभा में चुनाव सुधार से जुड़े मुद्दे पर चर्चा कराई जाएगी।

बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि चुनाव सुधारों पर चर्चा कराने पर सहमति बन गयी है और उन्हें उम्मीद है कि बुधवार से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित होगी। विपक्षी गठबंधन के सदस्य शीतकालीन सत्र के पहले दिन से एसआईआर पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा कर रहे हैं, जिसके कारण सदन नहीं चल पा रहा है।

आईएनएस अरिदमन पनडुब्बी परीक्षण के अंतिम चरण में पहुंची

नयी दिल्ली, 02 दिसंबर। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने मंगलवार को कहा कि भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन अब परीक्षण के अंतिम चरण में है और इसे जल्द ही भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जायेगा।

अरिहंत श्रेणी की तीन परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बियों से संबंधित इस पनडुब्बी में विस्तारित मिसाइल पेलोड है, जिससे यह अगस्त 2024 में शामिल की गई आईएनएस अरिधाट की तुलना में अधिक लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है।

नौसेना प्रमुख ने बुधवार को होने वाले नौसेना दिवस समारोह से पहले वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि नौसेना के पहले चार राफेल विमानों के 2029 में आने की योजना है। विमानवाहक पोतों पर तैनात किए जाने वाले ऐसे 26 विमानों के लिए द्विपक्षीय समझौते को अप्रैल में फ्रांस के साथ अंतिम रूप दिया गया था, और समझौते के पांच साल बाद इनकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। इस पैकेज में हथियार, पुर्जे और सहायक उपकरण शामिल हैं और ये लड़ाकू विमान आईएनएस विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे।

अब झारखंड ...

- **चर्चा तो यह भी है कि कांग्रेस का झारखंड में विभाजन भी हो सकता है और हो सकता है कि एक बड़ा धड़ा हेमंत सोरेन की सरकार के समर्थन में आ जाए।**
- **राहुल के एक अन्य करीबी, के. राजू झारखंड के प्रभारी भी हैं, अब देखना है कि के. राजू झारखंड की इंडिया गठबंधन सरकार को कैसे बचा पाते हैं।**

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जब यह भी नहीं हुआ, तो सोरेन ने कहा कि कांग्रेस अपनी 61 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें उन्हें दे देती, तो भी वे 35 आदिवासी सीटों पर प्रचार कर लेते।

सोरेन का आरोप है कि कांग्रेस गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है। सोरेन का सवाल है कि "फिर मैं उनके साथ सरकार में क्यों रहूँ?"

उन्होंने अलूवीरा, जो राहुल गांधी की पसंद हैं और बिहार संभाल रहे हैं, के लिए कुछ कड़े और असंसदीय शब्दों का भी इस्तेमाल किया।

एआईसीसी प्रभारी अलूवीरा ने न किसी से मुलाकात की, न ही सामाजिक समीकरण या सहयोगियों को संभालने में कोई कूटनीतिक भूमिका निभाई।

सब पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी को अलूवीरा कहाँ से मिले थे।

झारखंड में, बहुमत का आंकड़ा 42 है, और अगर कांग्रेस के 16 और आरजेडी के 4 विधायक बाहर भी चले जाएँ तो भाजपा के 21 विधायक उनकी जगह ले सकते हैं।

और सबसे बड़ा खतरा यह है कि कांग्रेस के विधायकों के टूटकर सोरेन सरकार में शामिल होने की भी पूरी संभावना है।

झारखंड के प्रभारी के. राजू भी राहुल के नवरत्नों में से एक है। वे पूर्व अफसर हैं, जिन पर राहुल गांधी को बहुत भरोसा है।

अब देखना यह है कि वे झारखंड में कांग्रेस सरकार को कैसे बचाते हैं, जबकि कांग्रेस की संख्या लगातार तेज़ी से गिर रही है।

पावर ब्रेकफास्ट के बाद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मामले में भी "अंतिम निर्णय" राहुल गांधी ही लेंगे।

अगले छः माह में मुख्यमंत्री बनने की डीकेएस की उम्मीदों के लिए शायद यह शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि पिछले सप्ताह एनडीटीवी को बताया गया था कि गांधी मध्यावधि स्वैप से सहमत नहीं हैं। जो भी हो, आज डीकेएस के घर पर आयोजित ब्रेकफास्ट मीटिंग तीन दिनों में हुई दूसरी मीटिंग थी। जैसा कि कांग्रेस एक बार फिर शांति बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि वर्ष 2028 के चुनाव पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके। और पार्टी ने एक जुटता को रेखांकित करने वाली एक और 'सब ठीक है' दर्शाती हुई फोटो जारी की।

डीकेएस ने एक तस्वीर, जिसमें दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, के साथ "एक्स"पर लिखा, आज मेरे घर पर मुख्यमंत्री ने नाश्ता किया, ताकि हम राज्य के अच्छे शासन और कांग्रेस की सोच के अनुरुप, राज्य के निरंतर विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि कर सकें।" उन्होंने पत्रकारों से कहा, "हम कांग्रेस में एक आवाज़ हैं... पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, यह केवल मीडिया का कारनामा है।"

शनिवार को वे मुख्यमंत्री के घर पर मिले थे। उस समय, मेन्यू में इडली, उपमा और केसरी भात था, और शायद कॉफी भी थी। लेकिन जो चीज़ नहीं थी, वह था उनके विवाद का तत्काल समाधान। सूत्रों ने कहा कि दोनों ने सत्ता के हस्तान्तरण पर बात की, लेकिन तारीख पर सहमति नहीं बना पाए। डीकेएस का खेमा चाहता है कि यह जल्दी से जल्दी, यानी अप्रैल 2026 तक हो जाये, जबकि मुख्यमंत्री का पक्ष इसे जितना हो सके, टालने का इच्छुक है, यहां तक कि कार्यकाल के अंत तक भी।

सूत्रों ने कहा कि सिद्धारमैया का प्रस्ताव था कि वे कार्यकाल पूरा करें और फिर 2028 चुनावों में डीकेएस का समर्थन करें, अहिन्डा समुदाय में उनका राजनीतिक रूप से प्रभावशाली स्थान उनकी अच्छी संभावना बना सकता है।

अगर डीकेएस इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि कांग्रेस राज्य के दो सबसे बड़े वोट बैंक को अपने पक्ष में एकजुट कर सकती है, वोक्कालिगा समुदाय, जो पहले से ही शिवकुमार समर्थक है, तथा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का समर्थक अहिन्डा समुदाय। इस विवाद का केन्द्र एक समझौता है जो कथित तौर पर कांग्रेस की चौंकाने वाली 2023 की चुनावी जीत के बाद हुआ था - कि सिद्धारमैया और डीकेएस पांच साल का कार्यकाल साझा करेंगे, यानी दोनों में से प्रत्येक मुख्यमंत्री के तौर पर ढाई साल कार्य करेंगे। पिछले महीने यह आधा कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं दिखे, जिससे डीकेएस की ओर से दबाव बढ़ा, जिसमें वचन निभाने की बातें याद दिलाई गईं, और कांग्रेस के कुछ विधायकों ने दिल्ली जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे से सिद्धारमैया को पद छोड़ने के लिए कहने का आग्रह किया। सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने (अंततः) अपनी बात रखी।

सूत्रों ने बताया कि उन्होंने इस वादे को कायम रखने का आ ान किया, यह कहते हुए कि "यह वचन मेरे सामने दिया गया था... और इसे पूरा किया जाना चाहिए। अन्यथा, मेरे अपने राज्य में मेरी कोई विश्वसनीयता नहीं रहेगी।"

यह दूसरा अवसर है, जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस से इस मुद्दे को जल्दी ही सुलझाने का आग्रह किया है; पिछले सप्ताह उन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले इसे सुलझाने की बात की थी।

प्रधानमंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की शुरुआत पहले ही की जा चुकी है।

अधिकारियों के मुताबिक, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) जल्द ही साउथ ब्लॉक के अपने पुराने दफ्तर से निकलकर नए सेवा तीर्थ परिसर में शिफ्ट हो जाएगा। नया पीएमओ सेवा तीर्थ-1 परिसर से काम करेगा। इस परिसर में सेवा तीर्थ-2 में कैबिनेट सचिवालय होंगे और सेवा तीर्थ-3 राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) का दफ्तर होगा। इन बदलावों के साथ-साथ, केंद्र सरकार ने देश में राज भवनों का नाम बदल कर लोक भवन करने का भी एलान किया है। इसके पहले दिल्ली में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया था। वहीं, प्रधानमंत्री आवास अब लोक कल्याण मार्ग कहलाता है।

सेना ने इमरान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ही इमरान खान ने अपने लिए और पाकिस्तान के कमज़ोर मध्यम वर्ग के लिए बहुत कामयाबी से एक शानदार पोलिटिकल करियर बनाया। इमरान खान ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को कामयाबी की ऊँचाई पर पहुँचाया है और देश भर में उनके समर्थक हैं।

इमरान खान ने चुनाव लड़े और धीरे-धीरे समर्थन जुटाकर प्रधानमंत्री बने। शुरू में हालाँकि उनकी पॉलिटिकल पार्टी छोटी थी, लेकिन उन्होंने समर्थन जुटाया और फिर सेना ने उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया।

हालांकि जल्द ही, इमरान और सेना के शीर्ष अधिकारियों के बीच झगड़े शुरु हो गए। कुछ ही समय बाद, भ्रष्टाचार के आरोपों पर उन्हें सत्ता से हटाकर कड़ी सुरक्षा वाली सबसे बुरी जेलों में से एक जेल में डाल दिया गया। यहीं से उनका राजनीतिक सफर अचानक रुक गया।

कई दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चाएं और अफवाहें तेज थीं कि इमरान खान को जेल में मार दिया गया है। यह अफवाह इसलिए फैली, क्योंकि जेल प्रशासन लगातार उनके करीबी परिवार वालों को उनसे मिलने नहीं दे रहा था। बार-बार की अपील भी असफल रही। अंत में, पी.टी.आई. ने देशभर में विरोध प्रदर्शन किए और इमरान से मिलने की अनुमति की मांग की।

इमरान खान की लोकप्रियता ने पाकिस्तान की सेना के लिए दोधारी तलवार पैदा कर दी है। पहले तो सेना ने ही उन्हें उठाकर प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन बाद में इमरान की स्वतंत्र राजनीतिक शैली ने सेना के शीर्ष अधिकारियों को उनसे दूर कर दिया। विशेषकर आई.एस.आई. प्रमुख की नियुक्ति को लेकर बड़ा विवाद हुआ।

बाद में, इमरान ने सेना के बड़े अधिकारियों के निहित स्वार्थों पर चोट की, जिन्हें वर्षों से बिना रोक-टोक के पावर दी जाती थी और पॉलिटिकल अधिकारियों ने कभी उन पर रोक नहीं लगाई थी। इससे सेना पूरी तरह उनके खिलाफ हो गई और विपक्ष के साथ मिलकर उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया।

अब हालात ये हैं कि सेना वर्तमान नेताओं, जिनमें शाहबाज़ शरीफ भी शामिल हैं, से भी खुश नहीं है। आने वाले समय में पाकिस्तान में सत्ता की लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी, यह देखना दिलचस्प होगा।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, **कोटा कार्यालय :** पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:**-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908